में डाक वितरण प्रणाली की समीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो इस समीक्षा का क्या परिणाम रहा है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण व्यवस्था की आवधिक समीक्षा की जाती है। डाक नेटवर्क के विस्तार द्वारा डाक वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने और उसका विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में 1533 डाकघर खोले गए हैं। इनमें से 1302 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर ग्रामीण, जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों के लिए मंजूर किए गए थे।

डाकघरों के लिए भवनों का निर्माण

850. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई डाकघर किराए के मकानों में चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किराए पर राज्यवार कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ग) सरकार द्वारा डाकघरों के लिए भवनों के निर्माण के बारे में क्या प्रयास किए गए हैं और इस उद्देश्य के लिए गत तीन वर्षों के दौरान हर वर्ष कितनी राशि आवंटित की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) किराए के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान अदा किए गए किराए का सर्किलवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। चूंकि, राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते, इसलिए अनुबंध में जानकारी डाक सर्किल-वार दी गई है।

(ग) डाक प्रचालन कार्यों की कार्यकुशलता बहुत हद तक खुले और भलीभांति डिजाइन किए गए वनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अतः डाक विभाग की अनुक्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य में एक उद्देश्य डाकघरों और डाक कार्यालयों के लिए वनों का निर्माण करना भी है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाक विभाग ने वनों के निर्माण पर 155.55 करोड़ रुपए खर्च किए। डाकघरों और डाक कार्यालयों के लिए वनों के निर्माण के प्रयोजन से गत तीन वर्षों के दौरान आवंटित की गई धनराशि निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

1991-92	1992-93	1993-94
19.30	20.00	25.95

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान डाकघरों के लिए गए किराए का सर्किल-वार ब्यौरा (करोड़ रुपयों में)

सर्किल	1991–92	1992–93	1993–94
1. आन्ध्र प्रदेश	1.40	1.31	1.62
2. असम	0.24	0.24	0.25
3. बिहार	0.52	0.62	0.52
4. दिल्ली	0.23	0.28	0.26
5. गुजरात	0.61	0.63	0.63
6. हरियाणा	0.13	0.14	0.15
7. हिमाचल प्रदेश	0.16	0.17	0.18
8. जम्मू व कश्मीर	0.15	0.14	0.14
9. कर्नाटक	0.93	1.04	1.21
10. केरल	1.32	1.23	1.33
11. मध्य प्रदेश	0.60	0.56	0.65
12. महाराष्ट्र	2.84	3.07	2.42
13. उत्तर-पूर्व	0.25	0.28	0.29
14. उड़ीसा	0.49	0.47	0.57
15. पंजाब	0.24	0.24	0.25
16. राजस्थान	0.34	0.37	0.42
17. तमिलनाडु	1.47	1.40	1.52
18. उत्तर प्रदेश	1.11	1.25	1.37
19. पश्चिम बंगाल	1.25	1.06	1.22
कुल :	14.28	14.60	15.00

पेंशन तथा मनीआर्डरों की अदायगी न किए जाने संबंधी शिकायतें

881. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पेंशन तथा मनीआर्डरों की अदायगी न किए जाने के बारे में शिकायतें मिल रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी घटनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कितने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।